आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार

देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 22.08.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 547 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
- संसद का मॉनसून सत्र संपन्न; संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र को देश और सरकार के लिए बेहद सफल बताया।
- संसद ने युवाओं और संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित किया।
- देहरादून से दुबई के लिए एक दशमलव दो मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की पहली खेप रवाना की गई।

मंजूरी

केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 547 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से शहर के प्रमुख इलाकों में हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा और एससीएडीए ऑटोमेशन सिस्टम लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह परियोजना ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल बिजली व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि शहर की सुंदरता, सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन भी बेहतर होगा।

श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस काम को तय समय पर पूरा करेगी, ताकि लोगों को लगातार, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके।

परियोजना पूरी होने के बाद गंगा कॉरिडोर समेत शहर के प्रमुख क्षेत्रों में भूमिगत बिजली लाइनें होंगी और एससीएडीए सिस्टम से बिजली आपूर्ति पर पारदर्शी निगरानी और तुरंत सुधार की सुविधा मिलेगी।

मॉनसून सत्र संपन्न

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र भी कल सम्पन्न हो गया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 14 विधेयक पेश हुए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। श्री बिरला ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए व्यवधानों के कारण समय की बर्बादी पर नाराजगी व्यक्त की।

उधर, राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा उत्पन्न व्यवधान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद का मानसून सत्र देश और सरकार के लिए बेहद सफल रहा।

मंजूरी

संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित किया। यह विधेयक ई–स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है।

अस्थायी झील

उत्तरकाशी जिले में यमुना वैली के स्यानाचट्टी में भारी बारिश के बाद खड्ड में पानी और मलबा आने से यमुना नदी में अस्थायी झील बन गई है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के घरों और होटलों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि झील को सुरक्षित रूप से खोलने के लिए एनडीआरएफ की टीम साथ मौके पर पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि राहत और बचाव टीमें सभी जरूरी संसाधनों के साथ तैनात हैं और झील को जल्द ही सुरक्षित रूप से खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

स्पीड पोस्ट से प्रसाद

बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति ने डाक विभाग के साथ एमओयू के तहत श्रद्धालुओं को स्पीड पोस्ट से प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है।

समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भगवान बदरी विशाल और भगवान केदारनाथ के प्रसाद के 42 पैकेट डाक विभाग को सौंपकर सेवा की शुरुआत की।

समिति ने बताया कि पोस्ट ऑफिस प्रतिनिधि केनाल रोड स्थित बीकेटीसी कार्यालय से प्रसाद के पैकेट प्राप्त करेंगे। भगवान बदरीनाथ और केदारनाथ की दीर्घकालिक पूजा करवाने वाले श्रद्धालुओं को प्रति यात्रा वर्ष पांच से दस वर्ष तक प्रसाद भेजा जाएगा।

वार्षिक रखरखाव

टिहरी जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ सुरकंडा देवी स्थित रोपवे सेवा कल से वार्षिक रख–रखाव कार्यों के चलते 26 दिनों तक बंद रहेगी। रोपवे के प्रबंधक सी.बी. सिंह और समन्वयक नरेश बिजल्वाण ने जानकारी दी कि यह सेवा 17 सितंबर तक बंद रहेगी।

इस अवधि में रोपवे की वार्षिक जांच और निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें टॉवर, केबिन की मरम्मत के साथ–साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम का रख–रखाव शामिल है। निरीक्षण के दौरान लोड कैपेसिटी, विंड प्रेशर समेत अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच देश–विदेश के विशेषज्ञ इंजीनियरों द्वारा की जाएगी।

प्रबंधन ने सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है और असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है।

गढ़वाली सेब की पहली खेप

देहरादून से दुबई के लिए गढ़वाली सेब की पहली खेप रवाना की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने एक दशमलव दो मीट्रिक टन सेब की इस परीक्षण खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह पहल कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से संभव हुई है। परीक्षण से प्राप्त अनुभव शीत श्रृंखला प्रबंधन और लॉजिस्टिक ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

वाणिज्य सचिव ने कहा कि गढ़वाली सेब जैसे क्षेत्रीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना किसानों की आय बढ़ाने में अहम है। उन्होंने उत्तराखंड से बासमती चावल, मोटे अनाज, मसाले, राजमा, शहद, सेब, कीवी और सब्जियों के निर्यात की संभावनाओं का उल्लेख किया।

गौरतलब है कि एपीडा शीघ्र ही देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा और राज्य के उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने के लिए जैविक प्रमाणन व जीआई टैगिंग की सुविधा देगा। इसके साथ ही निर्यात परीक्षण के लिए एक समूह से समझौता भी किया गया है।

निर्यात संवर्द्धन के साथ सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी जिले में दो हजार 200 तिमरू पौधे लगाए गए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में उत्तराखंड से 201 करोड़ रुपये का कृषि निर्यात हुआ है और अब ताजे फलों, मोटे अनाज व जैविक उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में मिले सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखण्ड को 'खेलभूमि' के रूप में नई पहचान दी है।

उन्होंने अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधा, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आइस स्केटिंग रिंग संचालन, नई टिहरी में साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चीकरण, चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइम्बिंग सुविधा और राज्य के 95 विकासखण्डों में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल बनाने के प्रस्ताव रखे।

मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रथम खेल विश्वविद्यालय को अग्रणी संस्थान बनाने के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग और आर्थिक सहायता का आग्रह किया।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

एमओयू

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, रुड़की के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत सेना के रेजीमेंट मुख्यालय में विशेष अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र से सेना के जवान और अधिकारी अपने परिसर में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय ने शहीद सैनिकों की विधवाओं को फीस में छूट देने की योजना भी बनाई है। साथ ही गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजीमेंट के साथ भी ऐसे एमओयू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीईजी कमांडेंट ब्रिगेडियर के. पी. सिंह ने कहा कि यह पहल सैनिकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने और सेवा निवृत्ति के बाद कौशल विकास का अवसर देगी।